

समेकित बाल विकास कार्यक्रम के विविध आयाम

दिव्या रानी

शोधछात्रा—गृहविज्ञान वभाग।

तिलकामाझी विश्वविद्यालय

भागलपुर।



महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1985 में मानव संसाधन विकास के एक अंग के रूप में की गई है। इस विभाग को एक मंत्रालय का दर्जा 30 जनवरी 2006 को दिया गया। महिला एवं बच्चों का समस्त विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। यह मंत्रालय महिला एवं बच्चों की उन्नति के लिए योजना, नीतियाँ तथा कार्यक्रम का निर्माण करता है एवं इसके विकास हेतु कानून लागू कर इसमें सुधार के लिए भी जागरूक है। बच्चों के समस्त विकास के लिए इस मंत्रालय द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा कार्यक्रम “समेकित बाल विकास कार्यक्रम”(ICDS) का क्रियान्वयन किया गया। इस योजना का निर्माण 1947 में किया गया, और 1975 में इसे पूर्णतया लागू किया गया।

ICDS का विस्तृत रूप समन्वित बाल विकास योजना है। यह एक केन्द्र की योजना है। जिसका मूल उद्देश्य बाल विकास एवं महिलाओं के विकास के लिए बनायी गयी राष्ट्रीय योजना है। बालक एवं महिलाओं के प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल और अनौपचारिक शिक्षा के साथ पोषण की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। विकासशील देशों के निर्धन परिवारों में कुपोषण बहुत अधिकता से पाया जाता है जिसके फलस्वरूप बच्चे पर्याप्त उर्जा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनसंख्या में 13.1% हिस्सा रखने वाले 0-6 आयु समूह के बच्चों को पर्याप्त पोषण प्रदान करने हेतु 2 अक्टूबर 1975 को बच्चे ही भावी युवा एवं परिवार समाज एवं राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। के नारे के साथ भारत में समेकित बाल विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अति संवेदनशील एवं दूरस्थ क्षेत्रों में 6 वर्ष से कम आयु के कमजोर बच्चों तक शिक्षा स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बंधी समन्वित कार्यक्रम का प्रसार कर उनके जीवन स्तर को उँचा उठाना है।

ICDS महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलायी जाने वाली विष्व की सबसे बड़ी एवं सफल योजना है। यह योजना मुख्यतः केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त है। इस योजना के परिचालन एवं लागत के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकार इस कार्यक्रम के सफल निष्पादन एवं पोषण और स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। इस योजना के तहत अबतक 4 करोड़ बच्चों का नामांकन हो चुका है। हमारी केन्द्र सरकार इस योजना के निष्पादन पर 90% का खर्च वहन करती है। 2015-2016 के बजट में इस योजना के सफल निष्पादन एवं लागत के रूप में 14000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश भी इस योजना के सफल सम्पादन में योगदान दे रहे हैं। ICDS के उद्देश्य के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली को निम्न लाभ प्रदान करती है।

जो निम्न है।

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| (1) पूरक पोषण | (4) स्कूल पूर्व शिक्षा |
| (2) टीकाकरण | (5) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा |
| (3) स्वास्थ्य सेवा | (6) स्वास्थ्य जाँच सेवाएँ। |

इसके साथ ही पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस, टी0वी0, खसरा आदि का टीका भी उपलब्ध कराया जाता है। ICDS के अंतर्गत चलाये जाने वाले कार्यक्रमों का विस्तार काफी व्यापक और प्रभावशाली है।

ICDS विष्व के सबसे वृहत भारतीय जनकल्याणकारी योजना होने के बाद भी शिशुओं एवं बालकों की मृत्युदर में कमी एवं पोषण स्तर में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? गर्भवती माताओं द्वारा अविकसित तथा कम भार के बच्चों को जन्म दिया जाना, अनीमियां से पिड़ित होना, धातृ माताओ को अनीमिया से तथा पीलिया से ग्रस्त होना आदि।

आंगनबाड़ी संस्था ICDS के अंतर्गत महिला एवं बालविकास में मुख्य भूमिका निभाती है।

इसके कार्य विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है।

- (1) आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केन्द्र इसके अंतर्गत जिला अस्पतालों में गर्भवती महिला के जाँच एवं पंजीकरण की व्यवस्था करना।
- (2) प्रसव पूर्व जाँच एवं देखभाल।
- (3) पोषण एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखना।

- (4) विटामिनो एवं टीकाकरण का ध्यान।
- (5) बच्चों के जन्म का पंजीकरण।
- (6) बालक के 6 वर्ष तक होने पर पूरक आहार की व्यवस्था।

हर आंगनवाड़ी केन्द्र 6 माह से 6 वर्ष तक के 80 बच्चों को अपने परिधि में लेता है हर केन्द्र प्रतिदिन प्रतिबालक 2रू0 साथ ही पूरक आहार एवं स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था भी करता है। समेकित बाल विकास योजना के तहत दुलार से मुस्कान अभियान का कार्यक्रम भी होता है। इसका उद्देश्य ICDS के कार्यक्रमो को मजबूत बनाना तथा इससे होने वाले लाभों को जन समुदाय में पहुँचाना है। आंगनवाड़ी केन्द्र की मदद से प्रतिदिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य नयी रणनीति एवं अनुश्रवण प्रणाली द्वारा महिलाओं और बच्चों के बहुमुखी विकास उन्नति एवं परिवार कल्याण तथा पोषण से प्रयुक्त शिक्षा प्रदान करना है। ग्राम सम्पर्क अभियान भी ICDS के अंतर्गत ही आते है। इसमें महिलाओं के बहुमुखी विकास, पोषण एवं स्वावलंबन के लिए महिला विकास मंडल एवं गोष्ठियों का आयोजन करना तथा उन्हें पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बंधी जानकारी प्रदान करना है। ICDS ने बाल एवं महिला विकास में मुख्य भूमिका अदा की है एवं यूनीसेफ संस्था ने इसे अन्तरराष्ट्रीय योजना के स्तर पर रखा है। इसके कार्यक्रम की क्रियान्वय की सहमति भी प्रदान की है।

ICDS आने वाली योजनाओं में महिलाओं में घरेलू उत्पीड़न दहेज प्रताड़ना महिलाओं एवं किशोरियों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार बालक अधिकार हेतु कार्य एवं सामाजिक कुरीतियों से मुक्त भारत का निर्माण भी शामिल है।

संदर्भ ग्रंथ सूचि:—

1. मानव संसाधन विकास महिलाओं और विकास विभाग। वार्षिक रिपोर्ट 1995-96 पटि-4 भारत सरकार नई दिल्ली 5-6
2. कपिल यू निगरानी और आईसीडीएस योजना में सतत शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए एक मॉड्यूल, भारतीय बाल चिकित्सा। 1989, 26 :863-867
3. टंडन बी.एन. कपिल, यू. आईसीडीएस योजना माँ और बच्चों का स्वास्थ्य भारतीय बाल चिकित्सा के विकास के लिए एक कार्यक्रम 1991, 28 : 14-25-1428
4. आई. सी. डी. एस मृत्युदर पोषण स्तर।